बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 141

उचित माहौल जरूरी

गत सप्ताह सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की अपनी नीति पर और अधिक जोर देना आरंभ कर दिया। उसने इन वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया। वहीं इन वाहनों के चार्जर पर भी जीएसटी की दर 18 फीसदी से कम करके 5 फीसदी कर दी गई। नई दर 1 अगस्त से लागू होगी। सरकार ने 12 से अधिक लोगों को लाने ले जाने में सक्षम इलेक्ट्रिक बसों को स्थानीय प्रशासन द्वारा किराये पर लेने पर उसे जीएसटी से छूट प्रदान की है। इससे पहले बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की खातिर लिए गए ऋण के ब्याज पर आयकर में 1.50 लाख रुपये की छूट देने की घोषणा की गई थी।

दोनों कदम सरकार की मार्च में की गई फेम (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में तेजी) के दूसरे चरण की घोषणा के अनुरूप हैं। सरकार ने 2022 तक सरकारी परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये व्यय करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें से 1,000 करोड़ रुपये बुनियादी विकास के लिए चिह्नित किए गए हैं। इन वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनियों ने हालिया रियायतों का स्वागत किया है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के निजी इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी दर कम होने से इलेक्ट्रिक कारों और पेट्रोल तथा डीजल कारों की कीमत का अंतर घटेगा क्योंकि उन पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है।

चार्जरों पर जीएसटी में भारी कमी करके सरकार ने उस आलोचना का जवाब दिया है जिसमें कहा जाता रहा है कि सरकार फेम नीति के तहत चार्जिंग स्टेशन का मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना नहीं बना सकी है। परंतु अभी भी कई कारणों से इस पूरी कवायद पर संदेह के बादल हैं। पहली बात तो यह कि सार्वजनिक परिवहन में बदलाव लाकर उसे सीएनजी आधारित करने में ही काफी असमानता देखने को मिली है। दूसरी ओर निजी कार मालिकों को इन वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना आसान नहीं है। देश की राजधानी में नियमित रूप से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वालों को याद होगा कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब अचानक सार्वजनिक परिवहन सीएनजी आधारित किया गया तो कैसे फिलिंग स्टेशनों के इर्दगिर्द भीड़ लगी रहती थी। दिल्ली की सड़क से आखिरी डीजल बस हटने के 17 वर्ष बाद भी दिल्ली और आसपास पर्याप्त फिलिंग स्टेशन नहीं हैं। आज भी इन स्टेशनों पर भारी भीड़ लगी रहती है। देश में कुल मिलाकर 30 लाख सीएनजी वाहन हैं। इनमें गैस भरने के लिए देश भर में केवल 1,424 स्टेशन हैं। इनमें भी ज्यादातर दिल्ली और मुंबई में हैं। गत वर्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि अगले एक दशक में देश भर में 10,000 नए स्टेशन खोले जाएंगे लेकिन मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद भी इस योजना के बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। विनिर्माताओं ने चार्जिंग की लागत का भी जिक्र किया जो बिजली कीमतों से जुड़ी हुई है। चार्जिंग नेटवर्क बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक इन वाहनों का इस्तेमाल करने वालों को जल्दी ही इन प्वाइंट पर बिजली के लिए 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की लागत में काफी इजाफा होगा।

नियमित रूप से सामने आ रही रियायतें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार की नीति बुनियादी रूप से कमजोर है। एक और बात, इन वाहनों को लेकर सरकार काफी हद तक आयात पर निर्भर है, ऐसे में इस क्षेत्र में कितनी सफलता मिल पाएगी यह भी देखने वाली बात होगी। निरंतर संशोधन और अलग-अलग दरें जीएसटी ढांचे को सहज बनाने के विचार के प्रतिकूल हैं।

अजय मोहंती

मोदी की वापसी से स्तब्ध क्यों बाजार ?

यदि आज बाजार प्रतिभागी नाराज हैं तो शायद इसकी वजह यह है कि इतने वर्षों तक वे सपनों की दुनिया में जी रहे थे। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **देवाशिष बसु**

बजट के पहले सेंसेक्स 39,908 के स्तर पर था और अब तक करीब 2,500 अंक फिसल चुका है। कुल मिलाकर निराशा का भाव है। सेंसेक्स जून के अंत में उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। अगर आप सोशल मीडिया पर एक घंटा या इससे कुछ अधिक समय बिताते हैं तो आपको निरंतर इस सरकार की नीतियों की आलोचना सुनने को मिलेगी। यह सुनने को मिलेगा कि सेंसेक्स की इस ऊंचाई की आड़ में जो संपत्ति तिरोहित हुई, वह इन नीतियों की बदौलत ही हुई। ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं कि एक महीना भी नहीं हुआ और मोदी के दूसरे कार्यकाल से जुड़ी सारी सद्भावना समाप्त हो चुकी है। इसके लिए बजट के स्तरहीन होने को वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह भारतीय राजनीति का सबसे छोटा मधुमास साबित हुआ।

गत वर्ष बजट में सबसे बड़ा झटका दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर के रूप में सामने आया था। इस वर्ष लाभांश पर कर और पुनर्खरीद पर कर लगाया गया है। इसके अलावा प्रवर्तक हिस्सेदारी को घटाकर 65 फीसदी करने और सालाना 2 से 5 करोड़ रुपये अर्जित करने वाले लोगों के व्यक्तिगत आय कर में 3 फीसदी और 5 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक आय वालों पर लगने वाले कर में 7 फीसदी का इजाफा किया गया है। सरकारी खजाने के दम पर आराम का जीवन जी रहे राजनेता और अधिकारी अमीरों को आदेश दे रहे हैं कि वे गरीबों के लिए छोटा-मोटा बलिदान दें। हम इंदिरा गांधी के जमाने से ऐसा होते देख रहे हैं लेकिन इसके लिए जो समय चुना जाता है वह महत्त्वपूर्ण होता है। सरकार जहां समृद्ध कंपनियों और निवेशकों से अधिक से अधिक पैसा जुटाने में लगी हुई है, वहीं वह आर्थिक मंदी, रोजगार की कमी, निवेश में मामूली इजाफे और अपने व्यय में भारी इजाफे के लिए भी वही उत्तरदायी है।

सपनों की दुनिया से बाहर

आज यदि बाजार प्रतिभागी नाराज हैं तो इसकी वजह शायद यह है कि वे इतने वर्षों तक स्वप्न लोक में थे। नरेंद्र मोदी को जहां आबादी के हर तबके ने वोट दिया वहीं कारोबारी, वित्तीय और निवेशक समुदाय का उन्हें खास समर्थन हासिल रहा। पांच वर्ष तक फंड प्रबंधक, विश्लेषक और कारोबारी बदलाव के हर वादे में यकीन करते नजर आए। उन्होंने तमाम सही-गलत आंकड़ों तक को हजम कर लिया और अपने प्रजेंटेशन में उन्हें शामिल किया। इस तरह निवेशकों और फाइनैंसरों के समक्ष वृद्धि की गुलाबी तस्वीर पेश की गई। उन्होंने इस सरकार के हर समाजवादी कदम का स्वागत किया और उसे नये भारत की दिशा में उठा कदम बताया। जबकि ऐसे हर अवसर पर उन्हें सरकार को पिछली सरकारों के कदमों की याद दिलानी चाहिए थी।

उन्हें यह बात जरा भी अजीब नहीं लगी कि जिस सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के हर काम को बुरा बताया, वह न केवल उसी कांग्रेस सरकार के विचारों और योजनाओं को जारी रखे हुए है बल्कि उन्हें कई गुना विस्तार दे चुकी है। उनके लिए नोटबंदी एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम था, न कि व्यापक आर्थिक क्षति और बिना किसी पूर्व शर्त के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को वे एक अनिवार्य कदम मानते हैं, न कि पैसे डुबाने जैसा कदम। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने सरकार के हर दंडात्मक और जबरिया कदम को पारदर्शी और स्वच्छ भारत के लिए उठाया गया जरूरी कदम बताया।

बच्चों तक के लिए आधार अनिवार्य करना हो, वस्तु एवं सेवा कर या बिना कारण बताए कर छापे अथवा यह कहना कि नागरिकों को गोपनीयता का अधिकार नहीं है, ये सारी बातें उन्हें देश की स्वच्छता को लेकर प्रतिबद्धता नजर आती रहीं। उनका भरोसा इतना गहरा था कि वे देख नहीं पाए कि व्यवस्था की सफाई का दावा करने वाली सरकार धीरे-धीरे पारदर्शिता के सबसे अहम उपाय सूचना के अधिकार तक को खत्म कर रही है।

और फिर वे मेरे लिए आये

उपरोक्त गलत धारणा अब ध्वस्त हो चुकी है। इन्फोसिस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी और इस सरकार के समर्थक रहे मोहनदास पई कहते हैं कि सरकार देश के नागरिकों और कारोबारियों को एक ऐसी कर व्यवस्था से बचाने में नाकाम रही है जो एक गलत आकलन व्यवस्था और ध्वस्त अपील व्यवस्था के साथ काम कर रही है। किसी भी बड़े देश में ये दोनों व्यवस्थाएं एक साथ गड़बड़ नहीं रहतीं। कर अधिकारी हर किसी को कर वंचक और खुद को निगरानी समिति का सदस्य समझते हैं। हमने 30 से अधिक देशों में रिटर्न फाइल किए हैं लेकिन किसी देश में करदाताओं से इतना बुरा व्यवहार नहीं किया जाता है जितना भारत में। हाल ही में प्रकाशित एक आलेख में उन्होंने आलोचना करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकार का कर आतंकवाद समाप्त करने का वादा किया था लेकिन 50 फीसदी से अधिक लंबित कर विवाद पिछले दो वर्ष में उत्पन्न हुए हैं।

हम क्या जानते हैं?

मुझे हमेशा आश्चर्य हुआ है कि कारोबारियों और वित्तीय जगत के लोगों की आशाओं का आधार क्या था? आखिरकार मौजूदा सरकार देश की अब तक की सरकारों में सबसे अधिक गोपनीयता बरतने वाली सरकारों में शामिल है। यह सरकार कैसे काम करती है और क्या सोचती है इस बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। इसके लक्ष्य क्या हैं या फिर जबरदस्त चुनावी जीत के बाद यह किस खाके का अनुसरण करना चाहती है यह भी हमें नहीं पता। इसका चुनावी घोषणापत्र केवल कागज का एक टुकड़ा भर है, आधिकारिक आंकड़ों में छेड़छाड़ करके सरकार की सेहत दुरुस्त दिखाई जाती है, कोई श्वेतपत्र शायद ही देखने को मिले और तमाम राजनीतिक घोषणाएं जुमलों, अलंकारों और शब्द संक्षेपों से भरी रहती हैं। यहां तक कि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तक को बाहर बोलने की इजाजत नहीं रहती।

चाहे जो भी हो हमें सरकार के कदमों पर बात करनी चाहिए। अगर बाजार प्रतिभागियों और कारोबारियों ने सरकार के कदमों पर ध्यान दिया होता तो उनका भरोसा बहुत पहले टूट गया होता। सकारात्मक पहलू की बात करें तो विकृत पूंजीवाद में कमी आई है और फंसे कर्ज की वसूली के प्रयास हुए हैं। नकारात्मक पहलू देखें तो कांग्रेस की शैली के समाजवाद, प्रतिबंधों, कर आतंक, दंभ और संस्थाओं के पतन में इजाफा हुआ है। कुलमिलाकर यह तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने का तरीका नहीं है। अगर हम ऐसा मानते हैं, तो अपना मजाक खुद बना रहे हैं।

महज सूचकांक से नहीं लगता प्रगति का सही अंदाजा

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

वैश्विक स्तर पर अपने प्रदर्शन को आंकने के लिए आतुर देशों की नजर में वैश्विक सूचकांक तेजी से मापदंड बनते जा रहे हैं। खास तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए जद्दोजहद कर रहे विकासशील देशों के बीच इन सूचकांकों को लेकर खास आकर्षण देखा जा रहा है। सवाल है कि क्या इन सूचकांकों को किसी देश की प्रगति का सटीक संकेत माना जा सकता है? कई सूचकांकों में भारत के अलग-अलग प्रदर्शन को देखें तो इसमें संदेह की काफी गुंजाइश नजर आती है।

मसलन, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग के पांच स्थानों के सुधार के साथ 52वें नंबर पर पहुंच जाने को लेकर अच्छा-खासा रोमांच देखा गया है। इसी तरह कुछ समय पहले आई विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भी भारत का स्थान 100 से उछलकर 77 पर आ गया था। मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए कुछ सकारात्मक कदमों का इस जबरदस्त उछाल में योगदान रहा है। सरकार ने कारोबारी सुगमता रैंकिंग में शामिल मापदंडों पर नजदीकी नजर रखने के लिए एक कार्यबल गठित किया था। वाणिज्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, इन कोशिशों का नतीजा यह हुआ है कि पिछले चार वर्षों में भारत की रैंकिंग में 65 पायदान का सुधार देखने को मिला है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक को पहली बार किसी विकासशील देश में जारी किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जोशीले अंदाज में कहा कि 'एक नया नजरिया भारत की नई पहचान बन चुका है और हम एक अधिक समृद्ध देश बनते जा रहे हैं।'

उनके ये शब्द उत्तेजना जगाते हैं लेकिन मौजूदा हालात को बढ़ा-चढ़ाकर भी पेश करते हैं। हमारे पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) जैसे कुछ विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान हैं और हम वैश्विक स्तर पर आईटी एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र की बड़ी ताकत भी हैं। फिर भी यह सोचने वाली बात है कि भारतीय दूरसंचार उद्योग 5जी सेवाओं की शुरुआती तैयारियों के मामले में चीन, कोरिया एवं अमेरिकी कंपनियों पर ही आश्रित है। दवा क्षेत्र से इतर भारतीय कंपनी जगत शोध एवं विकास के मद में बहुत कम खर्च करता है और शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जब कोई टिप्पणीकार या विश्लेषक चीन की वैश्विक तकनीकी महारत का जिक्र नहीं करता है। चीन का शोध एवं विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय भारत की तुलना में आठ गुना है।

इसके बावजूद निस्संदेह यह सरकार नवाचार को बढ़ावा देने में सही मायने में रुचि ले रही है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने भी नीतिगत परिवेश में सुधार और बौद्धिक संपदा अधिकारों के आवंटन एवं परीक्षण में लगने वाला समय कम करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि कुछ खास सूचकांकों में प्रदर्शन सुधारने पर ध्यान देने भर से मनचाहा नतीजा नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है। कारोबारी सुगमता रैंकिंग में प्रदर्शन सुधरने के बावजूद एफडीआई प्रवाह में कोई खास अंतर नहीं आया है (असल में यह घट ही गया है)। इसी तरह नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधरने से वह अचानक वैश्विक स्तर पर तकनीकी चैंपियन नहीं बनने जा रहा है क्योंकि ऐसी उपलब्धियां एकाकीपन में नहीं होता है।

इन दिनों बढ़ रही सूचकांकों की भीड़ में से किसी पर भी नजर डालें तो एक पैटर्न दिखेगा। इन सूचकांकों में अमेरिका, स्कैंडेनेविया, जर्मनी, चीन, ताइवान और सिंगापुर शीर्ष स्थानों पर मौजूद होते हैं। ये देश न केवल कारोबारी सुगमता एवं नवाचार जैसे मानकों पर काफी आगे हैं बल्कि मानव विकास सूचकांक और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मापदंडों पर भी उनकी स्थिति काफी मजबूत है।

अकेले मानव विकास सूचकांक को ही देखें तो भारत लगातार पीछे खिसकता जा रहा है। वर्ष 2018 में भारत 189 देशों में से 130वें स्थान पर रहा और एक साल पहले की तुलना में उसकी रैंकिंग में केवल एक स्थान का ही सुधार हुआ था। हालत यह है कि भारत कई पैमानों पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और सहारा क्षेत्र के अफ्रीकी देशों से भी पीछे रहा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की स्थिति 180 देशों में से 78वें स्थान पर ही है जो एक साल पहले के 81वें स्थान से मामूली सुधार ही दिखाता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग दो स्थान की गिरावट के साथ 180 देशों में से 140वीं पर खिसक गई है।

अनूठे सूचकांकों के मामले में भी भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं है। विश्व खुशहाली सूचकांक को ही लीजिए। इसमें फिनलैंड के लोगों को सबसे खुशहाल बताया गया है। लेकिन छह महीने तक सूरज नहीं देख पाने वाले और अजीब तरह के खानपान वाले लोगों को भला इतना खुश क्यों होना चाहिए? दूसरी तरफ अतुल्य भारत, खूबसूरत पर्यटक स्थलों एवं दुनिया की बेहतरीन खानपान वाली जगह होते हुए भी भारत की 140वीं रैंकिंग खटकती है। खुशहाली रिपोर्ट में भारत भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे मौजूद है।

हमारी कंपनियों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है। संवेदना सूचकांक में कंपनियों का आकलन आंतरिक संस्कृति, सीईओ के प्रदर्शन, नैतिकता पालन और सोशल मीडिया मौजूदगी के आधार पर किया जाता है। आजकल कंपनी प्रबंधन के बीच संवेदना काफी पसंदीदा शब्द है। शीर्ष 20 संवेदनशील कंपनियों में एक भी भारतीय कंपनी शामिल नहीं है। वहीं सबसे कम संवेदनशील कंपनियों की 20 कंपनियों की सूची में भारत की आठ कंपनियां जरूर शामिल हैं।

इसका मतलब है कि सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधारने के लिए कार्यबल बनाने से कहीं अधिक प्रयास करने होंगे। लेकिन यह भी तय है कि इन मानदंडों पर सुधार लाए बगैर प्रगति के रास्ते पर बढ़ पाना भी मुश्किल होगा।

कानाफूसी

रास न आई घरवापसी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल की घर वापसी तो कराई लेकिन इसे पार्टी में सभी खुश नहीं हैं। दरअसल प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल और त्रिपाठी के रिश्ते बहुत पहले से खराब चल रहे हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय सिंह सतना लोकसभा सीट से बहुत मामूली मतों से हार गये थे। उस वक्त उन्होंने अपनी हार के लिए त्रिपाठी को जिम्मेदार ठहराया था जो सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और अब भी हैं। उधर त्रिपाठी गत वर्ष के विधानसभा चुनाव के दो दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम बैठे थे। यही कारण है कि सतना कांग्रेस के नेता भी नारायण त्रिपाठी का विरोध कर रहे हैं। इस बीच पार्टी की प्रतिक्रिया पूरी तरह नपीतुली है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि कमलनाथ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो भी कर रहे हैं, स्थानीय इकाइयों को उसे स्वीकार करना होगा।

आपका पक्ष

दूषित भोजन व पानी से अरबों का नुकसान

प्रदूषण के कारण देश को वर्ष 2016-17 में करीब 7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। फाउंडेशन फॉर मिलनेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) और रिसर्च फर्म थॉट ऑर्बिट्रेज के एक अध्ययन में कहा गया है कि भोजन व पानी के दूषित होने से 7,37,457 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह राशि देश के कुल जीडीपी का 4.8 प्रतिशत है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधारे गए तो यह नुकसान वर्ष 2022 तक 9,50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। अध्ययन के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान दूषित भोजन व पानी के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज का कुल अनुमानित खर्च 32,941 करोड़ रुपये था। दूषित भोजन व पानी की वजह से सबसे अधिक फैलने वाली बीमारियों में डायरिया, सांस की बीमारी तथा अन्य संक्रामक रोग शामिल हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि देश गरीबी तथा भुखमरी से जूझ रहा है वहीं दूषित भोजन व पानी के कारण अरबों रुपये बरबाद हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए सरकार विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है जिसमें बड़ी धनराशि खर्च होती है। इसके बाद भी दूषित भोजन व पानी का सेवन कर बीमार होने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। सरकार ने हर घर पानी की योजना की शुरुआत की है। इस पहल से हर घर में पेयजल तो पहुंच जाएगा लेकिन वह पीने लायक होगा इसकी गारंटी नहीं है। कई बार नलों से आने वाले पानी के दूषित होने की शिकायत भी मिलती रहती है। अत: सरकार को दूषित भोजन व पानी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए नीति बनानी चाहिए।

दीपिका शर्मा, नई दिल्ली

एक रिपोर्ट के अनुसार देश को दूषित भोजन-पानी से 7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

बारिश के दिनों में सावधानी जरूरी

बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तथा इस मौसम में मच्छर जनित बीमारियां अधिक होती हैं। दिल्ली में अबतक मलेरिया के 80 तथा डेंगू के 34 मामले सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े नगर निगम ने एक रिपोर्ट में जारी किए हैं। दिल्ली में पिछले साल डेंगू के 2,798 मामले दर्ज हुए थे तथा इस बीमारी से चार लोगों की मौत हो गई थी। बारिश के दिनों में जहां तहां पानी जम जाता है जिससे मच्छर के लार्वा आसानी से पनपते हैं। वहीं बारिश के दिनों में मच्छरों के लिए तापमान अनुकूल रहता है। शहरों के अलावा ग्रामीण जगहों में मलेरिया के अधिक मामले सामने आते हैं क्योंकि खुली जगह तथा खेत खलिहान, नलियों में पानी जमने से मच्छरों की संख्या काफी बढ़ जाती है। डेंगू व मलेरिया बीमारी से बचने के एहतियाती कदम अभी से उठाने होंगे। आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने घर के आसपास पानी जमने न दें जिससे मच्छर का लार्वा नहीं पनप सके। जहां कहीं गड्ढे में पानी जमा हो वहां कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाए। सरकार विज्ञापनों के जरिये सावधानी बरतने की सलाह समय-समय पर देती रहती है। इसमें घरों के गमले, पुराने टायर, डिब्बे आदि में पानी जमने से रोकने को कहा जाता है। सरकार के साथ-साथ लोगों को भी मच्छर को पनपने से रोकना होगा तथा जहां मच्छर पनप रहे हों उन्हें नष्ट करना होगा।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।